RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 346
दि. 19.04.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


## संक्षिप्त समाचार

### 'ओछी राजनीति करके विपक्ष ने बिल पारित नहीं होने दिया', महिला आरक्षण बिल पारित ना होने पर तमिलनाडु में बरसे ढट



केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण संसोधन बिल लोकसभा में शुक्रवार को पारित नहीं हो सका। इस असफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान तमिलनाडु में सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के विरोध को लेकर द्रमुक पर कड़ा प्रहार किया है।

## महिला आरक्षण से परिवारवाद तक, पीएम का विपक्ष पर चौतरफा हमला, आधी आबादी को दिलाया भरोसा

(जीएनएस)।

संसद में 'महिला आरक्षण विधेयक' के गिरने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने को प्रधानमंत्री ने सामान्य विधायी विफलता नहीं, बल्कि विपक्ष द्वारा की गई 'भ्रूण हत्या' करार दिया है। भावुक स्वर में राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों ने अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की करोड़ों बेटियों के सपनों का गला घोंट

महिलाओं के समर्थन में भावुक संदेश और संकल्प

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जानते हैं कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां इस समय दुखी हैं और वे खुद भी इस दुख में शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह प्रयास न रुकेगा, न थमेगा और उनका आत्मबल अजेय है। उन्होंने कहा कि आगे भी मौके आएंगे और आधी आबादी के सपनों व देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को हर हाल में पूरा किया जाएगा।

आधी आबादी को हक देने पर विपक्ष को क्रेडिट देने की पेशकश

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने संसद में भी कहा था कि आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, वे इसका श्रेय विज्ञापन छपवाकर विपक्ष को दे देंगे। इसके बावजूद, उनके मुताबिक, महिलाओं को दकियानूसी नजरिए से देखने वाले लोग अपने रुख पर अड़े रहे और पीछे नहीं हटे। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानून की लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस की नकारात्मक और एंटी रिफॉर्म सोच के खिलाफ बड़ी लड़ाई बताया और कहा कि देश की बेटियां इस सोच का करारा जवाब देंगी।'

डीएमके और टीएमसी पर मौका गंवाने का आरोप

पीएम मोदी ने कहा, 'डीएमके के पास तमिलनाडु से ज्यादा लोगों को संसद तक पहुंचाने और राज्य की आवाज मजबूत करने का मौका था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी के पास पश्चिम बंगाल के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का अवसर था, जिसे वह भुना नहीं सकी।'

कांग्रेस ने पहले भी किया विरोध–

पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल का विरोध कर कांग्रेस ने खुद को एंटी रिफॉर्म पार्टी साबित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले भी प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार, डिजिटल भुगतान, जीएसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण, अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक खत्म करने और समान नागरिक संहिता जैसे कदमों का विरोध किया है।

देश की 100 प्रतिशत नारीशक्ति का आशीर्वाद– पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66 प्रतिशत वोट नहीं मिले हों, लेकिन उन्हें देश की 100 प्रतिशत नारीशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को खत्म किया जाएगा और विपक्षी दल महिलाओं की संसद और विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हर सुधार को रोकना, लटकाना और भटकाना ही उसका कार्य संस्कृति रही है।

कांग्रेस पर 'एंटी रिफॉर्म' और भ्रामक राजनीति के आरोप

पीएम मोदी ने कहा कि 'महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है

## राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर पर रोक, कब होगी अगली सुनवाई?

(जीएनएस)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों में ऋक्रक्र दर्ज करने के अपने ही मौखिक आदेश को फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट ने माना है कि संभावित आरोपी का पक्ष सुने बिना और उसे नोटिस दिए बिना इस तरह का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

दरअसल, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने शुक्रवार को खुली अदालत में याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश सुनाया था। लेकिन इस आदेश के टाइप होने और हस्ताक्षर होने से ठीक पहले, कोर्ट ने 'जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2014) के एक पुराने फैसले का संज्ञान लिया।

किस आधार पर कोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक

इस फैसले के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी भी कार्यवाही में जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इसी कानूनी बिंदु के आधार पर अदालत ने अपने आदेश को रोक दिया।

'BJP का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

'BJP का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

याचिकाकर्ता के गंभीर आरोप और 'ब्रिटिश' नागरिकता का दावा

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर इस याचिका में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं:

विदेशी कंपनी का मालिकाना हकः याचिका के अनुसार, राहुल गांधी ने अगस्त 2003 में ब्रिटेन में 'M/S Backops Ltd' नामक एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी।

ब्रिटिश नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशनः दावा किया गया है कि कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता 'ब्रिटिश' बताई थी और उनका पता लंदन और हैम्पशायर का दर्ज है।

एनुअल रिटर्न का विवरणः याचिका में कहा गया कि अक्टूबर 2005 और 2006 में भरे गए कंपनी के वार्षिक रिटर्न में भी उनकी नागरिकता ब्रिटिश ही दिखाई गई थी, जिसे बाद में 2009 में भंग कर दिया गया

कानूनी उल्लंघनः याचिकाकर्ता का तर्क है कि राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंक खातों और कंपनी की जानकारी तो दी, लेकिन नागरिकता छिपाई

## नोएडा हिंसा का 'मास्टरमाइंड' चढ़ा पुलिस के हत्थे, मजदूरों को उकसाने वाले आदित्य की तमिलनाडु में गिरफ्तारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा में हुए श्रमिक उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपनी पहचान बदलकर रह रहा था।



पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य आनंद ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली थी और बाल कटवा लिए थे। नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड

पुलिस का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देकर मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने में आदित्य की मुख्य भूमिका थी।

और कौन-कौन थे हिंसा के मुख्य आरोपी?

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पूरे मामले को एक 'दुर्भावनापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित गतिविधि' करार दिया है। उन्होंने बताया कि इस हिंसा को भड़काने में मनीषा चौहान, रूपेश राय और आदित्य आनंद के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं।

जांच में क्या क्या खुलासा हुआ?

सुनियोजित साजिशः हिंसा से तीन दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। डिजिटल नेटवर्कः डीसीपी शैव्या गोयल के अनुसार, विरोध प्रदर्शन से पहले 80 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। भटकाने की रणनीतिः इन ग्रुप्स में वेतन वृद्धि या मजदूरों की मांगों पर चर्चा करने के बजाय, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और भीड़ जुटाने की योजना साझा की जा रही थी।

### होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला, भारतीय जहाज पर फायरिंग की खबर, ईरान ने बंद किया रास्ता

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद, र३१ं३ ङ्ग ल्ङ्ग१४९ को ईरान द्वारा अस्थायी रूप से खोलने की बात कही, फिर दोबारा असमंजस वाली



स्थिति पैदा हुई और आखिर में ईरान ने ट्रंप की अनर्गल बातों के चलते इसे वापस बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके ठीक पहले शनिवार को कम से कम आठ तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से गुजरे। वहीं, दिन में बाद में, इसी रास्ते से गुजरने वाले दो व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की खबरें सामने आई।

## सदन में बिल गिरा तो सड़कों पर फूटा गुस्सा! लखनऊ में 'नारी अधिकारों' के अपमान पर भड़कीं महिलाएं

**विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने कार्यलय से महिलाओं के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस और सपा कार्यालय के बाहर पहुंचीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.**

(जीएनएस)।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के खिलाफ सदन में विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया. इसके चलते बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया. अब विपक्षी दलों के इस रवैये के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर फूटता नजर आ रहा है. लखनऊ के गोमतीनगर में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने कार्यलय से महिलाओं के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस और सपा कार्यालय का घेराव करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

प्रदर्शन करने वालीं महिलाओं ने क्या कहा?

प्रदर्शन कर रहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को सदन में गिराकर कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास किया है, जो अत्यंत निंदनीय है.

महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: गोपाल राय

प्रदर्शन में मौजूद अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास न होना केवल एक विधेयक का गिरना नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों का ठहर जाना है, जो हर उस स्त्री ने देखे हैं जो अपने अस्तित्व को केवल चार दीवारों





तक सीमित नहीं रखना चाहती. इस महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, जो भारतीय संविधान में निहित समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है.

विरोध करने वाले सांसदों के आचरण की संवैधानिक समीक्षा की जाए

ऐसे में कुछ सांसदों द्वारा इस विधेयक के विरोध में मतदान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है. यह आचरण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बाधा के रूप में देखा जा सकता है तथा जनभावनाओं के विपरीत भी है. मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले सांसदों के आचरण की संवैधानिक एवं नैतिक दृष्टि से समीक्षा कराई जाए तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए.

### दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

इ८ रङ्गँ३ ङ्४ं१

गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। स्टेशनों पर होने



वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इन ट्रेनों को प्रमुख स्टेशनों जैसे आनंद विहार और नई दिल्ली से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है।

## महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक पास न होने पर सीएम रेखा गुप्ता का प्रोटेस्ट, कार्यक्रम में काली पट्टी पहन जताया गुस्सा

(जीएनएस)।

राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के ठीक एक दिन बाद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में काली पट्टी पहनकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने इस घटना को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ा झटका करार दिया।

लोकसभा में विधेयक विफल, बढ़ा राजनीतिक तनाव

महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। इस विफलता ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण सुनिश्चित करना था, लेकिन समर्थन के अभाव में यह पारित नहीं हो पाया।

विधेयक के गिरने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में काली पट्टी पहनकर विरोध दर्ज कराया। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों से जुड़ा था, जहां उन्होंने अपने संबोधन में इस घटना को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "बड़ा झटका" बताया।

'महिलाओं को हर हाल में प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए'

रेखा गुप्ता ने कहा, "देश में महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक मतभेदों के कारण इस महत्वपूर्ण मुद्दे में देरी नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार, लंबे समय से लंबित यह मांग अब और टाली नहीं जानी चाहिए।"

## लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों का एक और साथी दिल्ली से गिरफ्तार, दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही दबोचा

**आतंकियों के एक और साथी मैजुल को नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर निवासी मैजुल दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही पकड़ा गया। इस पर युवाओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जोड़ने का आरोप। यह है लखनऊ आतंकी गिरोह का सातवां साथी जिसे दबोचा गया।**

लखनऊ। (जीएनएस)। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के एक और साथी को नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान बिजनौर के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल पुत्र शौकीन के रूप में हुई है। आरोपित दक्षिण अफ्रीका में नाई का काम करता था। साथ ही भारत में आतंक फैलाने के लिए युवाओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ जोड़ रहा था।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पिछली तीन अप्रैल को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से चार आतंकियों साकिब, अरबाब, विकास व लोकेश को गिरफ्तार किया था। इनके पास से सात मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।

इन मोबाइल फोन में आग लगाकर दहशत फैलाने, खिलौना कार से विस्फोट करने जैसी कई आतंकी वारदातों के वीडियो बरामद किए गए



थे। इन्हीं वीडियो में एक वीडियो ग्रुप काल का भी था। इसमें दुबई निवासी आकिब एके-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में मैजुल के अलावा उवैद मलिक व आजाद भी शामिल थे। मैजुल ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से इस वीडियो को पोस्ट किया था। इसके बाद बिजनौर पुलिस ने थाना नांगल में मुकदमा दर्ज कर इसकी तलाश शुरू की थी। साथ ही एटीएस की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने मैजुल, आकिब व आजाद की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया था।

शनिवार को मैजुल जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया। इसकी सूचना बिजनौर पुलिस को दी गई। बिजनौर पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आकिब व आजाद वर्तमान में सउदी अरब में हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आकिब और आजाद की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रुप वीडियो काल से आए घेरे में

हथियारों के प्रदर्शन वाली ग्रुप वीडियो काल की जानकारी सामने आने के बाद गिरफ्तार आतंकी साकिब ने पूछताछ में बताया था कि आकिब ने दुबई से पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उसका संपर्क कराया था।

इसके बाद उसने अरबाब, विकास व लोकेश सहित कई अन्य युवाओं को आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ जोड़ा था। इस मामले में अभी तक साकिब, अरबाब, विकास, लोकेश, उवैद मलिक, जलाल हैदर, समीर उर्फ रुहान को गिरफ्तार किया जा चुका है।

### इतिहास में दर्ज हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी एक विशेष मैदान पर अपने 100 मैच पूरे करने वाली टीम बनी

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही उत्साह है। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरी, तो उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया।

आज का यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं, बल्कि आरसीबी के जज्बे और उनके घरेलू मैदान के प्रति वफादारी का एक बड़ा 'सेंचुरी' उत्सव है।

आरसीबी आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने किसी एक विशेष मैदान पर अपने 100 मैच पूरे किए हैं। बेंगलुरु का यह मैदान और आरसीबी की टीम एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं।

2008 में इसी मैदान से आईपीएल के सफर की शुरूआत हुई थी, और आज 2026 में आरसीबी ने यहां मैचों का शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स इस सूची में दूसरे नंबर पर है, लेकिन चिन्नास्वामी के 'लाल समंदर' (फैंस) ने आज बाजी मार ली है।

# राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला:बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं माना; याचिकाकर्ता बोला- सीजेआई से शिकायत करेंगे

लखनऊ , (जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ऋऋक दर्ज करने का अपना ही आदेश बदल दिया है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी किया।

कोर्ट ने बताया कि शुक्रवार (17 अप्रैल) को सुनवाई हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है? वकीलों ने नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं बताई थी। इसके बाद ऋऋक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया था।

हालांकि, आदेश टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को परखा। उन्होंने पुराने केसों की स्टडी में पाया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

यह याचिका कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाते हुए विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम आदि में केस दर्ज होने की मांग की है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद विग्नेश ने कहा- राहुल गांधी के खिलाफ ऋऋक दर्ज करने का फैसला वापस लेने की शिकायत हम उखक से करेंगे।

कल केस दर्ज करने और उइक से जांच के आदेश दिए थे

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ ऋऋक दर्ज करने का आदेश दिया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था- ऋऋक दर्ज करके मामले को उइक को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि, इससे पहले 28 जनवरी, 2026 को टढ-टछअ कोर्ट ने विग्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने मंत्रालय से ह्यटॉप सीक्रेटह्ल फाइलें ली थीं सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश की थीं।

विग्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। इनसे संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

शुक्रवार को सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से वकील डॉ. बीके सिंह पेश हुए थे। केंद्र सरकार का पक्ष वकील एसबी पांडेय ने रखा। याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की तरफ से बिंदेश्वरी पांडेय कोर्ट पहुंचे थे।

रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुआ था केस

यह शिकायत शुरू में रायबरेली में विशेष टढ/टछअ कोर्ट में दायर की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था।

इसके बाद लखनऊ में टढ/टछअ कोर्ट ने 28 जनवरी, 2026 को याचिका खारिज कर दी। फिर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पहले ऋऋक दर्ज करने का आदेश, फिर अपना आदेश पलट दिया।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए।

सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था- 'हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है। 'याचिका में कहा गया था, 'कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे।'

याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्योरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था।

राहुल के खिलाफ यूपी में 3 केस

राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है। यह मामला 2018 का है। जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का आरोप लगाया था। 20 फरवरी, 2024 को कोर्ट ने राहुल को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। शुक्रवार, 17 अप्रैल को कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को बार-बार स्थगन आदेश लेने पर कड़ी चेतावनी दी है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

लखनऊ की एक अदालत में राहुल पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया था।

हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। बूलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने यह परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि अदालत से दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया।

मोदी सरनेम केस में गई थी सांसदी

मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।

# 69000 शिक्षक भर्ती: रउ में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी लखनऊ में फिर दिखाएंगे दम, परिजन भी होंगे शामिल

(जीएनएस)।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 22 अप्रैल को फिर से राजधानी लखनऊ में दम दिखाएंगे। इस बार अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके परिजन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं इस मामले में अलग-अलग आंदोलन कर रहे संगठन भी एकजुट होंगे।

अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका दो फरवरी से राजधानी के ईको गार्डेन में अनवरत धरना चल रहा है। किंतु सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोई पहल नहीं कर रही। इससे मामला टलता जा रहा है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है।

अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई 19 मार्च को होनी थी लेकिन हुई नहीं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड है। इससे सभी अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। हमने 22 अप्रैल को महाआंदोलन करने का फैसला लिया है। सुशील कश्यप ने बताया कि सभी जिले में समन्वयक बनाकर ब्लाक स्तर पर सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी आ सकें।

आंदोलन में शामिल सुमित कुमार, विक्रम, अमित मौर्या आदि ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला, सब हमारे पक्ष में है। फिर भी हमारे साथ न्याय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं। सरकार जल्द इस मामले में ठोस पहल नहीं करती है तो आंदोलन व्यापक होगा।

# 'भाजपा का पतन शुरू हो गया', महिला आरक्षण बिल फेल होने पर ममता बनर्जी का दावा, मोदी सरकार के लिए बोली बड़ी बात

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कराने में विफल केंद सरकार पर ममता बजर्नी ने कहा भाजपा का "पतन" शुरू हो गया है।

'वे दूसरों के सहारे सत्ता में बैठे हैं'

पश्चिम बंगाल में हावड़ा केउलूबेरिया में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया, भाजपा "हार चुकी" है और मोदी सरकार केवल सहयोगियों के दम पर सत्ता में है। "भाजपा का पतन शुरू हो गया है। हमने भाजपा को पराजित कर दिया है। उन्हें अपमानित किया गया है। उनके पास अपनी कोई बहुमत नहीं है। वे दूसरों के सहारे सत्ता में बैठे हैं।"

महिला विधेयक आरक्षण बिल हुआ फेल

ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी केंद्र के लोकसभा में 2029 से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक पारित न कर पाने के बाद आई है। याद रहे इसमें 2029 से विधायिकाओं में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण और लोकसभा सीटें 816 करने का प्रावधान था। इसके समर्थन में 298 वोट पड़े और 230 वोट इसके खिलाफ गए, लेकिन इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी।

'तभी तो बाबू को आज राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा'

ममता बनर्जी ने कहा, 'कल से पतन शुरू हो गया है, तभी तो बाबू को आज राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है।' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है, वह 'दो लोगों के सहारे' बैठी है, और यह सहारा हटने पर सरकार गिर जाएगी।'

ममता बोलीं- भाजपा अब 'धड़ाम धड़ाम' हो रही है

मुख्यमंत्री ममता ने यह भी बताया कि उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा को हराने के लिए अपने सांसदों को दिल्ली भेजा था। उन्होंने दावा किया कि 20 से अधिक अन्य पार्टियों के सांसद भी भाजपा के खिलाफ गए। बनर्जी के अनुसार, भाजपा अब 'धड़ाम धड़ाम' हो रही है।

परिसीमन के जरिए भाजपा देश को तोड़ रही

ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उन्हें 'बम से भी नहीं डराया जा सकता, गोली से भी नहीं।' उन्होंने दृढ़ता से कहा कि 'जन्म हुआ है तो मौत होगी' पर वह भाजपा से लड़ना नहीं छोड़ेंगी। ममता ने परिसीमन बिल को भाजपा की देश तोड़ने की मंशा का परिणाम बताया।

लोकसभा में पहले से ही 36% महिला सांसद हैं

महिला आरक्षण पर ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी में लोकसभा में पहले से ही 36% महिला सांसद और राज्यसभा में 46% महिला सांसद हैं। उन्होंने जोर दिया कि वह 1998 से इस लड़ाई में शामिल हैं और भाजपा को उनसे सीखना चाहिए।

बिस्वा में सरमा बोले- ममता बनर्जी पीएम मोदी से डरती हैं

कूचबिहार में चुनावी दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ममता पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से डरती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि अगर बंगाल में भाजपा आई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी।

"इखढ पश्चिम बंगाल से ळटउ का कर देगी सफाया"

हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि जैसे भाजपा ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 'हमेशा के लिए बंद कर दिया' है और बिहार में भी ऐसा ही होगा, उसी तरह बंगाल में टीएमसी को भी 'हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।' उन्होंने विपक्ष के दावों को 'दावे बड़े होते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता' कहकर खारिज कर दिया।

# 'राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान

**महाराष्ट्र से सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बहुत प्रभावशाली नेता हैं.**

(जीएनएस)।

देश की संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से पास नहीं हो पाया. इस बीच राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा था कि हम इस बिल को यहीं हराएंगे.

वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल देश के लोकतंत्र बचाने के आंदोलन का नेतृत्व किया है. राहुल गांधी देश के बहुत प्रभावशाली नेता हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने कल एक बहुत बड़ी जंग को जीत में बदल दिया है.

मराठी भाषा को लेकर क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि हर राज्य में अपनी मातृभाषा अनिवार्य करनी चाहिए. यह सरकार की नीति है और आरएसएस की भी नीति है कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसमें क्या गलत है? महाराष्ट्र की मातृभाषा

मराठी है. वहां काम करने, पढ़ाई करने और आजीविका कमाने वालों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए.

यह एक राजनीतिक साजिश थी- संजय राउत

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण विधेयक एक राजनीतिक साजिश थी, और यह विफल हो गई. यह मोदी और उनके गुट के पतन की शुरूआत है. वे महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने ढंग से मतदाताओं के गठबंधन में हेरफेर करके सभी चुनाव जीतना चाहते थे. संसद में उनकी ये योजनाएं धराशायी हो गईं. वे लोकसभा सीटों की संख्या मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सके, लेकिन उन्हें संविधान की शक्ति और अपनी वास्तविक ताकत का एहसास हो गया है.

उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का पद केवल 16 सांसदों के बहुमत पर टिका है. अगर ये 16 भी कम हो गए, तो उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर बाहर जाना पड़ेगा. आज के घटनाक्रम का यही अर्थ है. मोदी का पतन जल्द ही होने वाला है. मेरी बात याद रखना. राहुल गांधी ने उन 16 सांसदों के गले में फंदा डाल दिया है.

संजय राउत ने बिल को लेकर क्या कहा?

संजय राउत ने बिल पेश होने से पहले कहा था कि महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन का खेल चल रहा है, वह बहुत गंभीर है. बीजेपी अपने अनुसार पॉलिटिकल मैप बनाने की कोशिश कर रही है. उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच बीजेपी ने मतभेद पैदा कर दिया है. दक्षिण के राज्यों को कमजोर बना दिया है. दो-चार राज्यों की ताकत इतनी बढ़ा दी है कि वही देश की राजनीति तय करेंगे.

# 543 सीटों पर क्यों अटका 33% आरक्षण? किसकी गलती, किसका खेल

(जीएनएस)।

लोकसभा में 17 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो सका था। इस बिल में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (18 अप्रैल) को कैबिनेट मीटिंग में कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन न करके गलती की है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिस पर आम सहमति नहीं बन पाई? क्या यह महिलाओं के हक की लड़ाई

थी या सीटों के गणित का खेल? जिम्मेदार कौन है और आगे क्या होगा। आइए, 10 प्रमुख सवालों (FAQs) के जरिए इस पूरे विवाद को सवाल-जवाब से समझने की कोशिश करते हैं।

संसद में महिला आरक्षण पर महा-मंथनः बड़े सवाल

1. क्या राजनीतिक मतभेद महिलाओं के प्रतिनिधित्व में देरी का असली कारण हैं?

जी हां, भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा 1996 से लटका हुआ है। आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि हर बार 'कोटा के भीतर कोटा' (ओबीसी आरक्षण) और परिसीमन की शर्तों पर आकर राजनीतिक दल दो धड़ों में बंट जाते हैं। इस बार भी सरकार इसे 'परिसीमन' से जोड़कर लागू करना चाहती थी, जबकि विपक्ष इसे 'बिना शर्त' तुरंत लागू करने की मांग पर अड़ा रहा। यही वैचारिक मतभेद देरी की मुख्य वजह है।

सरकार और विपक्ष दोनों ही महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन तरीका अलग है। सरकार चाहती है कि आरक्षण जनगणना + परिसीमन के बाद लागू हो, जबकि विपक्ष तुरंत लागू करने या डइउ डेटा के साथ लागू करने की मांग कर रहा है।

जबकि 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में साफ लिखा गया था कि नया जनगणना पूरा हो, उसके आधार पर परिसीमन किया जाए, यानी सीधे 543 सीटों पर तुरंत लागू करने का कोई प्रावधान नहीं था। 2023 में पास हुआ बिल में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था Article 334A इसमें लिखा गया है:

आरक्षण तभी लागू होगा जब

कानून लागू होने के बाद पहली जनगणना पूरी हो

और उसके बाद परिसीमन किया जाए

उसी परिसीमन के आधार पर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी

यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा

इसलिए अभी की 543 सीटों पर सीधे लागू करना उस कानून के खिलाफ हो जाता है।

2. बिल अटकने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?

लोकतंत्र में संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन संविधान संशोधन जैसे अहम फैसलों के लिए विपक्ष का साथ भी अनिवार्य है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास साधारण बहुमत तो है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 352 का आंकड़ा (2/3 बहुमत) नहीं था। यहां जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, सरकार की इस मामले में कि वह सर्वसम्मति बनाने में विफल रही, और विपक्ष की इस मामले में कि उन्होंने संशोधन के मूल ढांचे पर असहमति जताई।

3. क्या विपक्षी दलों को इस सुधार का समर्थन करना चाहिए था?

आदर्श रूप में, महिला सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति होनी चाहिए। हालांकि, विपक्ष का तर्क (जैसा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा) यह है कि वे 'महिला आरक्षण' के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उस 'प्रक्रिया' के विरोधी हैं जो जनगणना और सीटों की संख्या बढ़ाने (परिसीमन) से जुड़ी है। विपक्ष का मानना है कि आरक्षण के नाम पर देश का राजनीतिक नक्शा बदलना गलत है।

4. क्या बिल को रोकना सशक्तिकरण के प्रति नकारात्मक संदेश है?

सामाजिक रूप से देखें तो यह निश्चित रूप से एक झटका है। लाखों महिलाएं राजनीति में अपनी हिस्सेदारी का इंतजार कर रही हैं। जब भी कोई ऐसा विधेयक गिरता है, तो जनता के बीच यह संदेश जाता है कि राजनीतिक दल अपने पावर गेम के लिए महिलाओं के अधिकारों को पीछे धकेल रहे हैं। हालांकि, विपक्ष इसे 'संवैधानिक ढांचे को बचाने की लड़ाई' के रूप में पेश कर रहा है।

5. क्या दलों को प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठना चाहिए या विरोध उचित है?

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में 'विरोध' भी एक संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी बिल में ऐसे प्रावधान हों जो भविष्य में क्षेत्रीय असंतुलन (उत्तर बनाम दक्षिण भारत) पैदा कर सकते हों, तो उस पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए, विरोध नीतिगत है या राजनीतिक, यह बहस का विषय है।

# थलपति जीतेंगे या हारेंगे? क्या डीएमके से छिन जाएगी तमिलनाडु की सत्ता,आया नया सर्वे

(जीएनएस)।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में अभिनेता-राजनेता थलपति विजय के चुनावी रण में उतरने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक्टर से राजनेता बने थलपति के फैंस उत्सुकता से यह जानने को बेचैन हैं कि क्या वह पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट, इन दो सीटों से जीत हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही लोग जानना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन सत्ता में वापसी होगी या नहीं? जूनियर विकटन के हालिया सर्वे में हैरान करने वाले परिणाम सामने आएं हैं।

थलपति विजय की क्या होगी जीत?

सर्वे के अनुसार विजय जैसे नए राजनीतिक चेहरों का उदय वोटर्स की प्राथमिकताओं को अप्रत्याशित तरीकों से नया आकार दे रहा है। हालिया सर्वे के आंकड़े के अनुसार एक्टर थलपति विजय पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों पर शानदार जीत हासिल करेंगे।

क्या DMK से छिन जाएगी की सत्ता?

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन सत्ता में बने रहने की स्थिति में दिख रही है,जूनियर विकटन का अनुमान है तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में ऊटड नेतृत्व वाला गठबंधन 121 सीटें हासिल कर बहुमत के आंकड़े (118) को पार करता दिख रहा है। ऊटड अकेले 97 सीटें जीत सकती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई (मार्क्सवादी) और विदुथलाई चिरुथिगल काची जैसे सहयोगी दलों का भी योगदान रहेगा।

अक्कअऊटड गठबंधन को कितनी मिलेंगी सीटें?

विपक्षी AIADMK गठबंधन को 83 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें अक्कअऊटड 75 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और पट्टालि मक्कल काची जैसे छोटे सहयोगी मामूली बढ़त बना सकते हैं, जो करीबी मुकाबले का संकेत है।

तमिलनाडु उट के तौर पर थलपति या स्टालिन कौन है पहली पसंद?

मुख्यमंत्री पद की पसंद के मामले में थलपति विजय ने सबको चौंका दिया है। सर्वे में 44% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है, जो ऊटड के एम.के. स्टालिन (28%) और AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (25%) से काफी अधिक है। सीमान को 3% लोगों का समर्थन मिला है, जिससे विजय की बढ़ती लोकप्रियता स्पष्ट झलकती है।

किस गठबंधन को कितने फीसदी मिलेगा वोट?

जनता की राय में, ऊटड गठबंधन को 36%, अक्कअऊटड गठबंधन को 33% और ळएड को 27% समर्थन मिलने का अनुमान है; नाम तमिलर

काची को 3% वोट मिल सकते हैं। पार्टी-वार वोट शेयर इस प्रकार है- DMK 37.50%, AIADMK 33.63%, TVK 24.71% और नाम तमिलर काची 2.71%।

सवाल यह भी कि क्या अकेले दम पर DMK बना पाएंगी तमिलनाडु में सरकार? सर्वे में यह भी सामने आया है कि खंडित जनादेश की आशंका के बावजूद, अधिकांश उत्तरदाताओं (55.9%) को एकल-पार्टी सरकार की उम्मीद है, जबकि 32.1% गठबंधन सरकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। केवल 12% लोगों को त्रिशंकु विधानसभा की संभावना दिखती है। हालांकि, 27 ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है, जो अंतिम परिणामों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

क्या DMK सरकार से संतुष्ट है तमिलनाडु की जनता? राज्य में सत्ता विरोधी रुझान भी सक्रिय है। 62% उत्तरदाताओं ने सरकार में बदलाव का समर्थन किया है, जबकि 38% लोग मौजूदा सरकार को जारी रखने के पक्ष में हैं। इससे साफ है कि DMK गठबंधन भले ही आगे हो, लेकिन उसे सत्ता विरोधी दबावों का सामना करना पड़ रहा है।

थलपति के चुनाव लड़ने से किसे हो रहा ज्यादा नुकसान?

एक दिलचस्प सर्वे में यह भी पता लगाया कि अगर विजय राजनीति में प्रवेश नहीं करते, तो नाम तमिलर काची को सबसे ज्यादा फायदा होता और उसे 30% से अधिक समर्थन मिलता। AIADMK और DMK को भी कुछ वोट बढ़ते, जिससे यह संकेत मिलता है कि TVK विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम से वोट खींच रही है।

तत्काल चुनावों से परे, भविष्य के राजनीतिक प्रभाव के मामले में भी विजय 47.25% के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद स्टालिन (24.9%) और पलानीस्वामी (15.79%) का स्थान है। के. अन्नामलाई का प्रभाव मात्र 1.28% दर्ज किया गया है।

कुल मिलाकर, DMK गठबंधन को मामूली बढ़त मिली है, लेकिन विजय की TVK का बढ़ता प्रभाव और AIADMK की निरंतर उपस्थिति इस चुनाव को बेहद प्रतिस्पर्धी बनाती है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर और बदलाव की मजबूत लहर के बीच, 23 अप्रैल का परिणाम राज्य की राजनीति में अपेक्षित निरंतरता और चौंकाने वाले बदलाव दोनों ला सकता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# सम्पादकीय

## एक्स पर पोस्ट लिखकर मायावती की भाजपा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर की सीधी चोट

महिला आरक्षण को लेकर मायावती का विरोधियों पर तीखा प्रहार मायावती का यह प्रहार सियासी दलों को आईना दिखाता है। वे कहती हैं कि वोट के लिए बहुजन समाज का इस्तेमाल होता है लेकिन हितों की रक्षा नहीं। दलित महिलाएं देश की आधी आबादी का हिस्सा हैं। शिक्षा रोजगार और राजनीति में उनकी भागीदारी कम है। महिला आरक्षण इसे बदल सकता है लेकिन उपकोटा जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि महिला आरक्षण मात्र कानून नहीं बल्कि सियासी हथियार बन गया है। महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले इस कानून ने सभी दलों को अपनी रणनीति पर पुर्नविचार करने को मजबूर कर दिया है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पाटा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर भाजपा कांग्रेस और समाजवादी पाटा पर सीधी चोट की है। उन्होंने कांग्रेस को गिरगिट तक कह डाला है। मायावती का कहना है कि कांग्रेस दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गो के मुद्दों पर दोहरा चरित्र अपनाती रही है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड कभी भरोसेमंद नहीं रहा। मायावती ने आरोप लगाया कि जब वेंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन वर्गो को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस इन वर्गो की बात कर रही है लेकिन यह महज राजनीतिक मजबूरी है।

मायावती ने अपने पोस्ट में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करती रही है। समाजवादी पाटा को भी उन्होंने पिछड़े वर्गो के प्रति उदासीन बताया। बसपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण कानून का लाभ एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए अन्यथा यह कानून मात्र दिखावा साबित होगा। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे इन वर्गो की महिलाओं के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिति करें। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस खबर को गहराई से समझने के लिए हमें पहले महिला आरक्षण अधिनियम के संदर्भ को देखना होगा। यह कानून 128 संशोधन विधेयक के रूप में 2023 में पारित हुआ था। लोकसभा राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें है। लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा जब परिसीमन होगा। इसी बीच मायावती का यह बयान राजनीतिक दलों के बीच आरक्षण के लाभार्थियों को लेकर हो रही बहस को तेज कर रहा है। बसपा हमेशा से दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण निर्णायक होते हैं वहां यह बयान बसपा की रणनीति का हिस्सा लगता है। मायावती का कांग्रेस पर गिरगिट कहना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीतियों को लागू तो किया लेकिन कई बार इसे कमजोर करने की कोशिश भी की। उदाहरण के तौर पर 1990 के मंडल आयोग की सिफारिशों के समय कांग्रेस ने विरोध किया था। वी पी सिह की सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया तो कांग्रेस ने इसे अदालत में चुनौती दी। मायावती का इशारा इसी ओर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने से कतरा गई।

2006 में प्रमोशन में आरक्षण बिल लाने की कोशिश हुई लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जब महिला आरक्षण आया तो कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के कोटे की बात कर रही है जो पहले कभी नहीं उठाई। यह राजनीतिक उलटपेर मायावती को चुभ रहा है।

# नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

**विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास**

**अगर आप लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है, यहां आपको पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल जाएगी.**

(जीएनएस)।

लखनऊः अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और अगली ट्रिप में लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है. इमामबाड़ों की भव्यता से लेकर बेगम हजरत महल पार्क की शानदार सैर तक, यहां आपको पर्यटन स्थलों से लेकर सफर की हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी, जो आपकी लखनऊ यात्रा के लिए काफी यादगार साबित होगी.

बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास

दरअसल, 18 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मानव सभ्यता से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि इनके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके. नवाबों का शहर लखनऊ धरोहरों का खजाना माना जाता है. यहां की ऐतिहासिक इमारतें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं. बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद घंटाघर, सतखंडा और बारादरी जैसी इमारतें आज भी शहर की ऐतिहासिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं. यहां रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचकर नवाबी दौर की वास्तुकला, तहजीब और परंपराओं का अनुभव करते हैं. तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि लखनऊ को क्यों देश की सांस्कृतिक राजधानी और विरासतों का गढ़ कहा जाता है, वहां कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है?

बड़ा इमामबाड़ा

लखनऊ में कुछ ऐसी इमारतें भी हैं, जो अपनी अनोखी बनावट के कारण आज भी लोगों को चौंका देती हैं. इनमें सबसे खास है बड़ा इमामबाड़ा. इसकी विशाल छत अपनी लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस निर्माण में न तो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और न ही लोहे का. बिना किसी खंभे के खड़ी यह छत इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती है. यही अनोखी बनावट देशभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. लोग यहां पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखते हैं और इसकी बनावट को देखकर अचंभित रह जाते हैं. बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने करवाया था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है.

बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण की क्या है दिलचस्प कहानी?

इतिहासकारों के और नवाबी खानदान से मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक इस भव्य इमारत का निर्माण वर्ष 1784 में भीषण अकाल के दौरान कराया गया था. इसे अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने बनवाया था, ताकि अकाल से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिल सके. इमामबाड़े का मुख्य हॉल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है. इसकी छत लगभग 50 मीटर लंबी और करीब 16 मीटर चौड़ी मानी जाती है. खास बात यह है कि इतनी बड़ी छत बिना किसी स्तंभ के खड़ी है, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक को दशार्ती है.

सीमेंट नहीं, पारंपरिक सामग्री से किया गया था निर्माण

निर्माण में उस दौर की पारंपरिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. इसमें लखौरी ईंटें, चूना (लाइम प्लास्टर), गुड़, उड़द की दाल और बेल के गूदे का मिश्रण उपयोग में लाया गया था. यह मिश्रण दीवारों और छत को मजबूती देने के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करता था. विशेषज्ञ बताते हैं कि छत को टिकाए रखने के लिए मेहराब तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें भार को दीवारों में बराबर बांट दिया जाता है. यही वजह है कि बिना खंभों के इतनी विशाल छत सदियों से मजबूती के साथ खड़ी है. आज बड़ा इमामबाड़ा न सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत उदाहरण भी है, जिसे देखने देश-विदेश से पर्यटक लखनऊ पहुंचते हैं.

'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा

नवाबी दौर की शानदार निशानी और 'मिनी ताजमहल' कहलाने वाला छोटा इमामबाड़ा का निर्माण अवध के तीसरे बादशाह नवाब मोहम्मद अली शाह ने वर्ष 1838 में कराया था. यह इमारत दरअसल एक इमामबाड़ा (सभा स्थल) के साथ-साथ उनका मकबरा भी है.

छोटा इमामबाड़ा

क्यों कहा जाता है 'मिनी ताजमहल'?

नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि छोटा इमामबाड़ा को 'मिनी ताजमहल' कहने के पीछे कई खास वजहें हैं. इसकी वास्तुकला में सफेद संगमरमर जैसी चमक और बारीक नक्काशी दिखाई देती है, जो ताजमहल की याद दिलाती है. इमारत के गुंबद, मीनारें के डिजाइन इसे शाही और भव्य रूप देते हैं. अंदर की सजावट में बेल्जियम के झूमर, रंगीन कांच और सुनहरी कलाकारी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी आंतरिक खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

रोशनी और सजावट है मुख्य आकर्षण

छोटा इमामबाड़ा को 'पैलेस ऑफ लाइट्स' भी कहा जाता है. खासकर मुहर्रम के दौरान यहां हजारों दीये और झूमर जलाए जाते हैं, जिससे पूरी इमारत रोशनी में जगमगाती नजर आती है.

पर्यटकों के लिए खास आकर्षण

छोटा इमामबाड़ा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. इसकी भव्यता और नफासत नवाबी दौर की समृद्ध संस्कृति और कला का जीवंत उदाहरण पेश करती है.

लखनऊ में गुमनाम, खास धरोहरें

हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर

हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर, भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावरों में से एक है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से अक्सर पर्यटक इसे नजरअंदाज कर देते हैं.

दिलकुशा कोठी

दिलकुशा कोठी लखनऊ के शांत कैंटोनमेंट (छावनी) इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक इमारत के अवशेष है. ब्रिटिश दौर की यह इमारत अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसकी वास्तुकला आज भी आकर्षित करती है. यह जगह अपनी वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जानी जाती है.

बेगम हजरत महल पार्क

बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ के हृदय स्थल हजरतगंज इलाके में स्थित है. यह पार्क परिवर्तन चौक के पास और होटल क्लार्क अवध के बिल्कुल सामने है. 1857 की क्रांति की वीरांगना की याद में बना यह पार्क इतिहास का अहम गवाह है.

रेजीडेंसी

लखनऊ में रेजीडेंसी शहर के केंद्र में कैसरबाग इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है. यह ऐतिहासिक स्थल हजरतगंज के काफी करीब है और गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है. 1857 के विद्रोह के निशान आज भी यहां की दीवारों पर देखे जा सकते हैं. यह जगह अपेक्षाकृत कम भीड़ वाली है. ऐसे में अगर आप कम भीड़ और शांति पसंद करते हैं तो यह जगह आपके बेहतर हो सकती है.

कैसे पहुंचे इन धरोहरों तक?

अगर कोई पर्यटक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है, तो इन जगहों तक पहुंचना काफी आसान है.

बेस्ट रूटः चारबाग से हुसैनाबाद क्षेत्र (बड़ा इमामबाड़ा, क्लॉक टॉवर) तक टैक्सी/ऑटो से 20झ्र30 मिनट.

मेट्रो विकल्पः लखनऊ मेट्रो से ट्रांसपोर्ट नगर से हजरतगंज तक सफर, फिर ऑटो/कैब

लोकल ट्रांसपोर्टः ई-रिक्शा और सिटी बसें आसानी से उपलब्ध

इमामबाड़ा टिकट की कीमत

बड़ा इमामबाड़ाः भारतीय पर्यटकः ₹50, विदेशी पर्यटकः ₹500

छोटा इमामबाड़ाः भारतीय पर्यटकः ₹25झ्र₹30 (लगभग) विदेशी पर्यटकः ₹300 (लगभग)

नोटः टिकट दरों में समय-समय पर बदलाव संभव है.

हुसैनाबाद ट्रस्ट ने पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल मशीन लगाया है, जिससे वह खुद भी इमामबाड़े के अंदर मौजूद मशीन से टिकट निकाल सकते हैं. उसके अलावा बारकोड से भी टिकट ले सकते हैं.

# भाषा, खानपान और इमारतों के लिए एक समृद्ध विरासत वाला शहर लखनऊ

लखनऊ। जुबां भी हमारी पहचान है। हम जितने अदब से आदाब बोलते हैं, उतना ही अपनापन "पहले आप" में लुटाते हैं। ये हमारी लखनवी संस्कृति की पहचान ही नहीं विरासत भी है। हमारे शहर की इमारतें, परिधान, कला और संस्कृति भी धरोहर हैं, जो दिन-प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है।

लखनऊ में स्वाद का भंडार है। यहां के खाने जैसा जायका कहीं और नहीं मिलता। यूनेस्को ने गत वर्ष नवंबर में इस शहर को "सिटी आफ गैस्ट्रोनामी" से सम्मानित कर इस बात को स्वीकार किया है। यहां चाट-टिक्की का अलग ही जायका होता है। फिल्म जगत का कोई भी कलाकार हो या फिर अन्य कोई मेहमान, वो लखनऊ आता है तो चाट और अन्य व्यंजनों का स्वाद अवश्य लेता है।

इतिहासकार पद्मश्री डा. योगेश प्रवीन ने अपनी किताब ह्यआपका लखनऊह्ण में लिखा है कि दूध और मैदे की बनी बाकरखानी रोटी को यहां के महमूद मियां ने शीरमाल की सूरत दी थी। ईरान और अफगानिस्तान का मशहूर कुलचा भी लखनऊ में आकर अलग स्वाद पा गया।

विश्व धरोहर दिवस वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1983 में यूनेस्को महासभा ने इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी।

हर इमारत की अलग कहानी...

लखनऊ में अनेक इमारते हैं। सबकी अलग कहानी है। यहां की नक्काशी का काम विख्यात है। छतों पर सफेद रंग की नक्काशी संगमरमर सी लगती है, लेकिन वह होती चूने की है। यह शंख और सीप के पाउडर को चूने में मिलाकर बनाई जाती है। बेल बूटों के अलावा चिकनकारी के पैटर्न भी दीवारों पर मिल जाते हैं।

नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासन काल में कोठी दर्शन विलास का निर्माण प्रारंभ कराया गया था। राज्य पुरातत्व निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार, 1832 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय में यह कोठी बनकर तैयार हुई थी। छतर मंजिल इलाके में बादशाह नासिरुद्दीन हैदर ने प्रियतमा कुदसिया महल के लिए यह महल बनवाया था।

19वीं सदी के चौथे दशक में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने कोठी गुलिस्ताने इरम का निर्माण कराया था। लाल बारादरी और छोटी छतर मंजिल के मध्य बनवाए गए इस महल का कुछ भाग शेष रह गया है। इस भवन पर यूरोपियन वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चौक में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा की विशिष्ट पहचान है तो कैसरबाग में छतर मंजिल भवन इंडो-इटालियन स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है।

# ईरान की गलती से चीन ने ले लिया सबक, एशिया के होर्मुज में छोड़े शिकारी, अमेरिका परेशान पर भारत की भी बढ़ी टेंशन

**एक तरफ ईरान में समंदर के अंदर माइंस का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया में बाली के पास एक संदिग्ध टॉरपीडो जैसी चीज मिली है. हैरानी की बात ये है कि इसमें चाइनीज डिवाइस लगा हुआ मिला है, जो भारत की भी टेंशन बढ़ाने वाला है जबकि अमेरिका को सीधी चुनौती है.**

(जीएनएस)।

इंडोनेशिया के लोम्बोक होर्मुज में एक बड़ा टॉरपीडो जैसा उपकरण मिला है, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने चीनी अंडरवाटर मॉनिटरिंग सिस्टम बताया है. यह खोज चीन की गुप्त जासूसी रणनीति को एक बार फिर बेनकाब कर रही है. पिछले हफ्ते गिली ट्रावांगन

द्वीप के उत्तर में एक मछुआरे ने 3.7 मीटर लंबा यह सिलेंडर आकार का उपकरण मछली पकड़ते समय जाल में फंसाया. इंडोनेशियाई नौसेना ने इसे जब्त कर जांच शुरू कर दी. नेवी के प्रवक्ता रियर एडमिरल तुंगगुल ने कहा कि हम इसकी उत्पत्ति, उद्देश्य और स्टोर किए गए डेटा की जांच कर रहे हैं.

ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉरपीडो कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इसमें जो डिवाइस लगाई गई है, वो डीप सी रियल टाइम ट्रांसमिशन मूरिंग सिस्टम है. इसके जरिये समुद्र के अंदर जासूसी की जा सकती है. इसे समुद्री रक्षा विशेषज्ञ एचआई सटन ने इसे चीनी 710 रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है. यह उपकरण समुद्र तल पर लंगर डालकर पानी की गहराई, तापमान, लवणता और धाराओं की रीयल-टाइम जानकारी सतह पर भेजता है.

अंडरवॉटर जासूसी क्यों कर रहा है चीन?

चीन की ऐसी डिवाइस का समुद्र की गहराइयों में मिलना कोई संयोग नहीं है, ये रणनीतिक स्ट्रेट में छिपकर घुसपैठ करने और दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करती हैं. हालांकि चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसकी ज्यादा व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल जब ईरान-अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था, तो ईरान के कुछ जहाजों को अमेरिकी टॉरपीडो ने डुबो दिया था. ये इस युद्ध में ईरान की बड़ी हार थी, ऐसे में चीन पहले ही ऐसी तैयारी कर चुका है. वो अमेरिकी पनडुब्बियों का पता समुद्र के अंदर ही सेंसर नेटवर्क बिछाकर लगाना चाहता है. लोम्बोक, मलक्का और हार्मुज, ये तीनों जलडमरूमध्य अब सिर्फ व्यापारिक रास्ते नहीं, बल्कि भविष्य के अंडरवाटर युद्ध के मैदान बन चुके हैं, जहां चीन चुपके-चुपके समुद्र के नीचे अपना जाल बिछा रहा है.

# पुलकित सम्राट-दिव्येंदु शर्मा के ग्लोरी का ट्रेलर रिलीज, बॉक्सिंग, बदला और मर्डर मिस्ट्री

मून जी

'ग्लोरी' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। पुलकित सम्राट और दिव्येंदु शर्मा स्टारर ये वेब सीरीज महत्वाकांक्षा, बदले और रहस्यमयी हत्या की कहानी को बेहद इंटेंस अंदाज में पेश करती नजर आ रही है। करीब 2 मिनट 27सेकंड के इस ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है।

हरियाणा बॉक्सिंग क्लब से शुरू होती है कहानी

ट्रेलर की शुरूआत हरियाणा के एक बॉक्सिंग क्लब से होती है जिसे चैंपियंस की फैक्ट्री कहा जाता है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसने अपने बेटे और भाई को खो दिया है।

उभरते बॉक्सर की रहस्यमयी हत्या पर आधारित है कहानी

सुविंदर विक्की द्वारा निभाया गया रघुबीर सिंह का किरदार एक सख्त लेकिन जुनूनी कोच का है जो अपने सपनों और विरासत को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वहीं उनकी बेटी गुड़िया जिसका किरदार जन्नत जुबैर ने निभाया है, एक हिंसक हमले का शिकार होती है। इसी बीच एक उभरते बॉक्सर की रहस्यमयी हत्या कहानी को और उलझा देती है।

मजबूत स्टारकास्ट और दमदार किरदारों की टक्कर

वेब सीरीज में आशुतोष राणा का किरदार विजू संघवान कहानी में टकराव को और तेज करता है जबकि सिकंदर खेर शक्तिगढ़ में अपना दबदबा जमाते नजर आते हैं। वहीं सायनी गुप्ता एक जांच अधिकारी के रूप में मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करती दिखती हैं। इनके अलावा यशपाल शर्मा, कश्मीरा परदेशी और कुणाल ठाकुर जैसे कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं।

'मुन्ना भैया' अवतार में फिर छाए दिव्येंदु शर्मा

ट्रेलर रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिव्येंदु शर्मा के किरदार की हो रही है, जिन्हें दर्शक 'मिजार्पुर' के मुन्ना भैया के रूप में पहचानते हैं। उनके इंटेंस लुक और एक्टिंग ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है।

ट्रेलर लॉन्च से पहले पुलकित सम्राट का रियल बॉक्सिंग मुकाबला बना चर्चा का केंद्र

-ट्रेलर रिलीज से पहले पुलकित सम्राट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच खेला।

-ये सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं थी बल्कि एक असली मुकाबला था, जिसमें पुलकित सम्राट ने पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया था। उन्होंने नीरज गोयत जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट की जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

ग्लोबल क्लब में शामिल हुए पुलकित सम्राट

इस मुकाबले के साथ पुलकित सम्राट प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लाइव फाइट करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ खुद को इंटरनेशनल स्टार्स जैसे टॉम हार्डी और जेक गिलेनहाल की लीग में खड़ा कर लिया है, जिन्होंने पहले इस तरह के स्टंट किए हैं।

रियल फाइट ने बढ़ाया वेब सीरीज का क्रेज

इस हाई-एनर्जी मुकाबले ने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया है बल्कि 'ग्लोरी' के एक्शन और इंटेंसिटी की झलक भी पेश की है। बॉक्सिंग रिंग में पुलकित सम्राट का प्रदर्शन ये दिखाता है कि वह अपने किरदार के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं।

क्या 'ग्लोरी' बनेगी अगली बड़ी हिट?

वेब सीरीज के ट्रेलर को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और यूनिक प्रमोशन स्ट्रेटजी को देखते हुए 'ग्लोरी' से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद ये सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

# पाकिस्तानी बच्चों में तेजी से फैला एचआईवी, अस्पताल की गलती का शिकार बने मासूम, कैसे खुली पोल?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान में एक डरावना मामला सामने आया है। जिसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही, असुरक्षित इंजेक्शन और सर्जिकल सामग्री इस्तेमाल करने की वजह से सैंकड़ों बच्चे HIV की चपेट में पाए गए हैं। इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रही BBC Eye के मुताबिक, नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच पंजाब प्रांत के तौनसा इलाके में कम से कम 331 बच्चे ल्क्ष पॉजिटिव पाए गए।

8 साल के बच्चे की मौत ने बढ़ाई चिंता

पीड़ितों में एक 8 साल का बच्चा, मोहम्मद अमीन भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। कई परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों को यह संक्रमण तहसील मुख्यालय (THQ) अस्पताल में इलाज के दौरान लगा। उनका आरोप है कि अस्पताल में इस्तेमाल की गई दूषित सिरिंजों के कारण यह गंभीर स्थिति बनी।

गुप्त फुटेज में दिखी खतरनाक लापरवाही

बीबीसी ने 2025 के अंत में 32 घंटे से ज्यादा का गुप्त वीडियो रिकॉर्ड किया। इस फुटेज में साफ देखा गया कि सिरिंजों को बार-बार मल्टी-डोज शीशियों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे एक मरीज से दूसरे मरीज तक संक्रमण फैलने का खतरा काफी बढ़ गया। कई मामलों में एक ही शीशी से अलग-अलग बच्चों को दवा दी गई।

सिर्फ सुई बदलना भी नहीं करता सुरक्षित

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर सिरिंज का बाकी हिस्सा दूषित है, तो केवल सुई बदलने से भी संक्रमण का खतरा खत्म नहीं होता। जांच में यह भी पाया गया कि अस्पताल में बुनियादी साफ-सफाई के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। कई बार स्टाफ को बिना दस्ताने के इंजेक्शन लगाते और मेडिकल कचरे

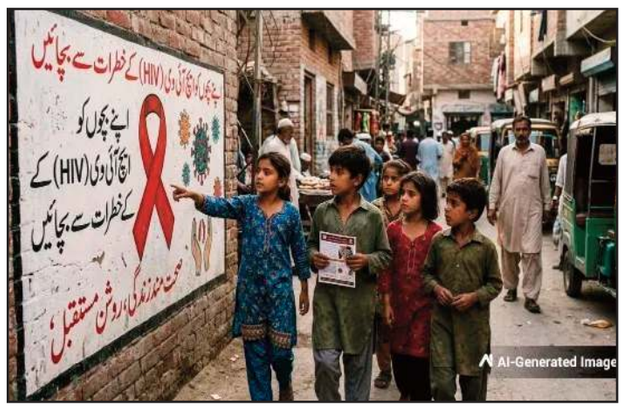


को गलत तरीके से फेंकते देखा गया।

कार्रवाई के बाद भी नहीं बदले हालात

हालांकि 2024 के अंत में एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने इस प्रकोप को THQ TÔu»»fsÔ HospitÔl से जोड़ा था, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई का वादा किया। मार्च 2025 में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. तैयब फारूक चंदियो को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा।

अधिकारियों ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल

बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई महीनों बाद भी असुरक्षित प्रथाएं जारी रहीं। हालांकि अस्पताल के अधिकारियों ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह फुटेज पुराना या सेटअप किया हुआ हो सकता है और अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित है।

नए अधिकारी का दावाः HIV पर फोकस

डॉ. चंदियो की जगह बुजदार को नियुक्त किया गया, जिन्होंने मार्च 2025 में पद संभालते ही कहा कि HIV उनका "मुख्य फोकस" है। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में संक्रमण कंट्रोल को लेकर "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई गई है। बुजदार ने बताया, "हमने पैरामेडिक्स और नर्सों के लिए HIV रोकथाम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं। सबसे अहम हमारा इंफेक्शन कंट्रोल सेक्शन है, जहां स्टाफ को ठीक से ट्रेन किया गया है।"

ज्यादातर मामलों में दूषित सुई जिम्मेदार

BBC Eye के डेटा एनालिसिस से पता चला कि आधे से ज्यादा मामलों में संक्रमण का कारण दूषित सुइयों को माना गया। सबसे अहम बात यह है कि संक्रमित बच्चों की बहुत कम माताएं ल्क्ष पॉजिटिव पाई गईं, जिससे यह साफ होता है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण मां से नहीं बल्कि अस्पताल में ही फैला।

# लखनऊ विकासनगर अग्निकांडः हाईकोर्ट सख्त, पूछा- 20 साल से सरकारी जमीन पर कैसे फल-फूल रहा था अवैध कब्जा?

(जीएनएस)।

लखनऊ के विकासनगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा कि 20 साल से ढहऊ की जमीन पर अवैध कब्जा कैसे बना रहा और अफसरों ने बिजली-गैस कनेक्शन कैसे होने दिए? 1200 झोपड़ियां जलने के बाद कोर्ट ने ऊ्ट और नगर निगम से 30 मई तक जवाब मांगा है. साथ ही, पीड़ितों को तुरंत भोजन, दवा और आश्रय देने का आदेश दिया है. बेघर हुए लोग अब भी मलबे पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं. राजधानी के विकासनगर सेक्टर-12 में हुए भीषण अग्निकांड की गूंज अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंच गई है. बुधवार की उस काली शाम ने न केवल 1200 परिवारों के सिर से छत छीन ली, बल्कि सिस्टम की गहरी नींद और सरकारी जमीनों पर दशकों से पल रहे अवैध अतिक्रमण की पोल भी खोल दी है. इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने एक तरफ जहां पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने का मानवीय आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाह अफसरों और अवैध कब्जा कराने वाले तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

हाईकोर्ट की कड़ी फटकारः 20 साल से क्यों सोता रहा अमला?

विकासनगर अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट ने शासन और प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने पूछा कि आखिर पीडब्ल्यूडी (ढहऊ) की चार बीघा बेशकीमती जमीन पर 1455 लोग पिछले 20 सालों से कैसे बसे हुए थे? कोर्ट ने हैरानी जताई कि इतने सालों तक सरकारी अमला क्या सो रहा था?

जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी कि आखिर बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी बस्ती कैसे बस गई. कोर्ट ने कंपनियों को भी लपेटे में लिया और पूछा कि इन अवैध झुग्गियों को बिजली और गैस कनेक्शन किस आधार पर और किन कंपनियों ने मुहैया कराए?

30 मई तक अफसरों को देना होगा हिसाब

कोर्ट ने इस मामले में लखनऊ के जिलाधिकारी, सीएमओ, नगर निगम और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को कड़ा निर्देश दिया है. इन सभी अधिकारियों को 30 मई तक कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि यह अतिक्रमण कैसे हुआ और अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. साथ ही, कोर्ट ने भविष्य के लिए आदेश दिया कि अफसर सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण न हो.

राहत और बचाव कार्य का ब्यौरा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अग्निकांड के पीड़ितों के लिए राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं. पीड़ितों के लिए भोजन, शुद्ध पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है. मौके पर अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और बेघर हुए लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है. नगर निगम ने जानकारी दी कि क्षेत्र में मोबाइल टॉयलेट और साफ-सफाई के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं.

आग का वो मंजर जिसने राजधानी को दहला दिया

बता दें कि बुधवार शाम विकासनगर के रिंग रोड किनारे स्थित झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते करीब 1200 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं. हालात इतने भयावह थे कि बस्ती में रखे लगभग 100 एलपीजी सिलेंडर एक के बाद एक धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा. दमकल की 22 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद रात 10 बजे तक आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सैकड़ों परिवारों का सब कुछ खत्म हो चुका था.

मलबे पर जिंदगी और अपनों की बेबसी

हादसे के बाद की तस्वीर बेहद मार्मिक है. जहां कभी झुग्गियां थीं, वहां अब सिर्फ राख और जले हुए लोहे के टुकड़े बचे हैं. इलाके की निवासी सुनहरा की आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों है. वे कहती हैं, 'हमारा सब कुछ जल गया. अब तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं. जो मदद मिल रही है, वो आस-पास के लोग दे रहे हैं.' सुनहरा जैसे सैकड़ों लोग अब भी उसी जली हुई जमीन पर प्लास्टिक की चादरें डालकर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है.

# लखनऊ में महिला आरक्षण बिल पर सियासी उबालः अपर्णा यादव ने जलाए सपा-कांग्रेस के झंडे, बोलीं- 'ये एक काली रात'

**महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने के बाद लखनऊ में अपर्णा यादव के नेतृत्व में सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए।**

(जीएनएस)।

लखनऊः महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में पास न हो पाने के बाद देश की राजनीति में तीखी हलचल शुरू हो गई है और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साफ तौर पर देखने को मिला। शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी के बीच उनके झंडे जलाए गए और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाया गया। बिल के गिरने के बाद बीजेपी ने इसे नारी शक्ति से जुड़ा मुद्दा बताते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज करने के संकेत दिए हैं।

देर रात सड़क पर उतरीं अपर्णा यादव

शुक्रवार रात महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास न होने पर अपर्णा यादव अपने समर्थकों और महिला आयोग से जुड़े पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के सामने पहुंचीं और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान अपर्णा यादव ने समर्थकों के साथ मिलकर सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए गए और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे।

इ ळअइडडछअरढडठरडफ़एऊ छक्ठडर डव टअ छक्डए

डस्रील्ल 'ल्ल,ॅब्ब्४ल्ल३ ३ङ्ग्ट!

क्ल्ल३ी१ू३५ी इ१ङ्ग्ी१२

विपक्ष पर सीधा हमला, 'नारी शक्ति' का मुद्दा प्रमुख

अपर्णा यादव ने प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग इस बिल को दिखावटी बता रहे हैं, उनका चेहरा भी दिखावटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि आम परिवारों की बेटियां और बहुएं आगे बढ़कर संसद तक पहुंचें। उनके अनुसार विपक्षी दल केवल अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं और नारी शक्ति उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

'काली रात' का जिक्र

अपर्णा यादव ने इस घटना को काली रात बताते हुए कहा कि अगर बिल पास हो जाता तो सुबह जश्न मनाया जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने नारी शक्ति अधिनियम को पास कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष के कारण यह संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल फिर खिलेगा।'

क्यों नहीं पास हो पाया महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के 131वें संशोधन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी। कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें 298 वोट पक्ष में और 230 वोट विपक्ष में पड़े। बिल को पास कराने के लिए 352 वोट आवश्यक थे, लेकिन यह आंकड़ा पूरा नहीं हो सका और बिल गिर गया, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया।

सपा कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन

लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिल पास न होने से महिलाओं के सशक्तिकरण का सपना टूट गया है और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है।

वहीं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा कि बीजेपी को प्रदर्शन के लिए कम से कम 12 महिलाएं भेजनी चाहिए थीं।

झंडा जलाने पर सपा ने उठाए सवाल

इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस झंडे को जलाया गया, वही आपकी पहचान से जुड़ा है और इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने अपर्णा यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार के नाम के बिना उनकी पहचान पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

देशभर में प्रदर्शन की तैयारी

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीजेपी अब देशभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। पार्टी इसे महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जोड़ते हुए विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा राजनीतिक तापमान बढ़ाएगा।

# चारधाम यात्रा का शंखनाद! अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट

(जीएनएस)। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने जा रहा है। इसी के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

अक्षय तृतीया के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं, केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इस बार रुद्रप्रयाग प्रशासन ने 'हाई-टेक' सुरक्षा चक्र तैयार किया है।

गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू हो गई है। धाम के तीर्थ पुरोहित अशोक सेमवाल ने बताया कि आज सुबह 8:30 बजे मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठान संपन्न किए गए। मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास 'मुखबा' से आज दोपहर 12:15 बजे गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है।

डोली शनिवार रात 'धरानी घाटी' (ऊँ१्ल्ल्ँ३) में विश्राम करेगी और कल सुबह गंगोत्री मंदिर पहुंचेगी, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर कपाट खोले जाएंगे। डोली विदाई के समय सेना के बैंड की धुनों और स्थानीय भक्तों के जयकारों से पूरा मुखबा गांव गुंजायमान रहा।

देश-विदेश से श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा के आरंभ के साथ ही उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्तों पर भक्तों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

केदारनाथ यात्रा के लिए हाईटेक निगरानी सिस्टम

इस साल केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने हाईटेक व्यवस्था लागू की है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक निगरानी के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।

हर जिले में 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम में पुलिस, प्रशासन और अन्य आवश्यक विभागों के कर्मचारी तैनात रहेंगे। यात्रा मार्ग पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं, वहीं केदारनाथ हाईवे और मंदिर परिसर में करीब 90 अतिरिक्त कैमरे भी स्थापित किए गए हैं।

यात्रियों को मिलेगी रियल टाइम मदद

नई तकनीक के जरिए प्रशासन अब यात्रियों पर लगातार नजर रख सकेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता भी उपलब्ध कराएगा। कंट्रोल रूम से ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए निर्देश दिए जा सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, यह हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान, श्रद्धा, आस्था और तकनीक का संगम

प्रशासन ने यात्रा मार्ग को सेक्टर और सब-सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की है, ताकि हर हिस्से की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और आपदा प्रबंधन की भी विशेष तैयारियां की गई हैं।

चारधाम यात्रा 2026 इस बार आस्था के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी संगम देखने को मिलेगा। जहां एक ओर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि-विधान से हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक सिस्टम को शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि इस बार की यात्रा कितनी सफल और सुरक्षित रहती है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड पूरी तरह से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार नजर आ रहा है।

# सीजफायद की घोषणा के बाद फिर नया ट्विस्ट, ईरान ने दोबारा किया बंद, टोल लगाने की जुगाड़ में फिर बढ़ेगा तनाव

(जीएनएस)।: लंबी जंग और फिर सीजफायर के बाद जैसे-तैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने पर तैयार हुआ था, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद एक बार फिर से ऐसी खबर आई जिसने होर्मुज पर पूरी दुनिया को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ट्रंप के अनर्गल बयान और ईरान की युद्ध रणनीति के बीच पूरी दुनिया का बाजार इससे प्रभावित हो रहा है। लिहाजा ईरान ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि होर्मुज को फिर से बंद किया जा रहा है। जिससे साफ है कि ईरान इस इलाके में अपना कंट्रोल चाहता है।

क्य हैं होर्मुज से गुजरने के नए नियम और शर्तें?

ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खोला जाएगा। अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में यह फैसला लिया गया है। ईरान ने शुक्रवार को होर्मुज को खोलने की बात कही थी लेकिन फिर इस पर असमंजस भरे बयान आने लगे। अब ईरान ने कहा कि सीजफायर के दौरान व्यापारिक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा।

2 मिलियन डॉलर फीस और बढ़ता विवाद

पिछले 2-3 हफ्तों में रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि ईरान कुछ जहाजों से इस रास्ते से गुजरने के लिए करीब 2 मिलियन डॉलर तक की फीस ले रहा है। इस बीच 17 अप्रैल 2026 को तेहरान में Sacrificed Girls रैली भी हुई, जहां महिलाओं ने मिडिल ईस्ट युद्ध में मारी गई महिलाओं को श्रद्धांजलि दी। इस तरह के घटनाक्रम बताते हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

उदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्बास अरागची के फैसले और ऐलान को "दुनिया के लिए शानदार दिन" बताया। उन्होंने कहा कि होर्मुज का खुलना वैश्विक व्यापार के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी दावा किया कि अमेरिका की सैन्य ताकत ने इस स्थिति को संभव बनाया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत पूरी होने तक दबाव बना रहेगा। साथ ही, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप अपनी बात पर कब तक टिके रहने वाले हैं। पाकिस्तान में अगले हफ्ते दूसरे दौर की शांति वार्ता संभावित है। अगर यह फिर से असफल होती है तो दुनिया को होर्मुज पर एक और तनाव का दौर झेलना पड़ सकता है।

फ्री नेविगेशन पर के रास्ते निकाल रहा भारत

28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका-इजरायल हमले के बाद शुरू हुए तनाव के दौरान ईरान ने भारत जैसे मित्र देशों को गुजरने दिया। हालांकि भारत ने किसी भी तरह का शुल्क देने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली लगातार यह कहता रहा है कि इंटरनेशनल सी-रूट्स पर फ्री और सुरक्षित आना-जाना होना चाहिए।

क्यों इतना अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए इसका खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार के लिए बेहद जरूरी है।

दुनिया का नाजुक शांति मुबारक

होर्मुज के खुलने से वैश्विक बाजारों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ईरान के नए नियम और फीस ने एक नया विवाद खड़ा दिया है। पिछले 2-3 हफ्तों के घटनाक्रम साफ दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति तो है लेकिन नाजुक स्थिति में। आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।

# गल्फ वारः खाड़ी युद्ध की तपिश से सुलगा यूपी-हरियाणा! इंडस्ट्रियल बेल्ट में क्यों टूटा मजदूरों के सब्र का बांध?

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के औद्योगिक इलाकों में इन दिनों भारी अफरा-तफरी का माहौल है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का सब्र अब जवाब दे गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है रसोई गैस की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। महंगाई के इस ताजा झटके ने मजदूरों की पुरानी वेतन संबंधी मांगों की आग में घी डालने का काम किया है। आइए जानतें हैं जमीन पर हालात किस तरह बिगड़ते चले गए?

औद्योगिक बेल्ट में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतें हैं। खुले बाजार में गैस के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उसने गरीब मजदूरों के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में गैस की कीमतें 100 रुपये प्रति किलो से बढ़कर सीधे 600-700 रुपये प्रति किलोतक पहुंच गई हैं।

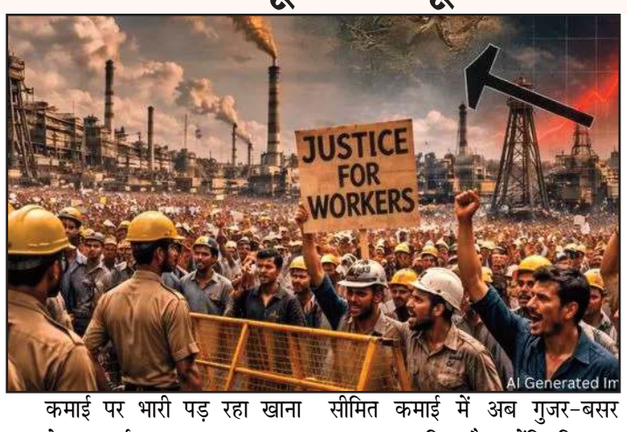





कमाई पर भारी पड़ रहा खाना पकाने का खर्च

दरअसल, जो मजदूर महीने में मुश्किल से 10,000 से 13,000 रुपए कमाते हैं, उनके लिए सिर्फ खाना पकाने का खर्च ही अब 2,500 रुपए के करीब पहुंच गया है।

महंगाई की चौतरफा मार

एनसीआर (NCR) के इलाकों में रहना पहले ही महंगा था, लेकिन अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। मजदूरों का कहना है कि उनकी सीमित कमाई में अब गुजर-बसर करना नामुमकिन है, क्योंकि किराया, बिजली और आने-जाने का खर्च (ट्रांसपोर्ट) लगातार बढ़ रहा है। न्यूनतम वेतन में संशोधन न होने की वजह से मजदूरों में सालों से गुस्सा भरा हुआ था, जिसे गैस की कीमतों ने सड़क पर ला दिया है।

कहां से शुरू हुई विरोध की चिंगारी?

यह विरोध प्रदर्शन किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देखते ही देखते पूरे औद्योगिक बेल्ट को अपनी चपेट में ले लियाः

हड़ताल की शुरूआतः प्रदर्शन की शुरूआत इस महीने की शुरूआत में मानेसरके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने की थी।

बड़ा आंदोलनः अब यह आंदोलन ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग के हब तक फैल चुका है। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर और महिलाएं 20,000 रुपये महीनेकी न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर डटे हुए हैं।

सरकार की कोशिशें नाकाम

तनाव को कम करने के लिए प्रशासन और राज्य अधिकारियों ने वेतन बढ़ाने की घोषणा तो की है, लेकिन मजदूर इससे संतुष्ट नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि प्रशासन द्वारा की गई बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उनकी जरूरतों के हिसाब से यह बेहद अपर्याप्त है।

# नहीं बन रही फिल्म 'हेरा फेरी 3'? अक्षय कुमार का बड़ा बयान, लोगों के सामने रखा ऐसा सच, फैंस की उम्मीदों पर पानी फिरा

(जीएनएस)।

फैंस लंबे समय से अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की 'हेरा फेरी 3' मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म में एक बार फिर से ये तीनों एक्टर अपना जादू चलाने के लिए तैयार थे लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार के बयान ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

'हेरी फेरी 3' को लेकर बड़ा अपडेट

अक्षय कुमार ने साफ कहा है कि फिलहाल फिल्म 'हेरा फेरी 3' नहीं बन रही है और कम से कम एक साल तक इस पर काम शुरू होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उन्हें खुद भी झटका लगा है लेकिन फिल्म को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।

ल्ीं ढौ१ 3

अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर दिया ऐसा बयान

-अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि तीनों एक्टर्स के बीच कोई समस्या नहीं है और वह साथ में 'वेलकम टू द जंगल' में काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में वह कैमरे पर बात नहीं कर सकते जिनमें एग्रीमेंट्स और कानूनी पहलू शामिल हैं।

-अपने अंदाज में अक्षय कुमार ने मजाकिया लहजे में कहा- शायद सब ठीक करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म 'हेरा फेरी 3' समय आने पर बन जाएगी, बस तब तक देर न हो जाए।





पहले से ही संकट में थी 'हेरा फेरी 3'

-परेश रावल के फिल्म छोड़ने से 'हेरा फेरी 3' पहले ही विवादों में आ गई थी। मई 2025 में उनके फिल्म से बाहर निकलने के बाद फैंस नाराज हो गए थे और 'बाबू राव' के बिना फिल्म न बनाने की मांग तक उठी थी। इसके बाद मामला और बढ़ गया जब अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर परेश रावल को लीगल नोटिस भेजे जाने की खबर सामने आई थी।

-हालांकि बाद में परेश रावल ने साइनिंग फीस वापस कर दी थी और फिर जून 2025 में उनकी फिल्म में वापसी की खबर आई। उन्होंने ये भी साफ किया कि अक्षय कुमार के साथ उनका कोई निजी विवाद नहीं है बल्कि ये सब एक गलतफहमी थी। वहीं फिल्म की देरी के पीछे एक बड़ा कारण कॉपीराइट विवाद भी है।

कानूनी लड़ाई और विवादों से जुड़ा है फिल्म का मामला

-मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर विजय कुमार ने निमार्ता फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमें फ्रैंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद सामने आया था। इसी कानूनी लड़ाई ने फिल्म की प्रगति को और धीमा कर दिया था।

-इस बीच अक्षय कुमार ने ये भी स्पष्ट किया था कि ये पूरा मामला कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है बल्कि गंभीर कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मुद्दे हैं, जिनकी वजह से फिल्म फिलहाल अटकी हुई है।

-कुल मिलाकर 'हेरा फेरी 3' फिलहाल कानूनी विवादों, कॉन्ट्रैक्ट इश्यू और पुराने मतभेदों के चलते अटकी हुई है। फिल्म बनेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन अभी के लिए फैंस का इंतजार और लंबा हो गया है।